

## भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और निधियों का प्रवाह 2019-20\*

वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से वित्तीय देयताओं में निवल वृद्धि को घटाने से प्राप्त हाउसहोल्ड अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन अंतराल 2019-20 में संकुचित हुए। जबकि हाउसहोल्ड और वित्तीय निगम निवल ऋणदाता बने रहे, वर्ष के दौरान गैर-वित्तीय निगमों और सामान्य सरकार की निवल उधारी में वृद्धि हुई। हालांकि, विदेशी संसाधनों पर निर्भरता एक साल पहले की तुलना में 2019-20 में कम हुई है। अन्य निक्षेपागार निगमों और अन्य वित्तीय निगमों से सामान्य सरकारी क्षेत्र में निवल प्रवाह 2019-20 में बढ़ा। अन्य वित्तीय निगमों के निवेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूति में था। मुद्रा और जमा हाउसहोल्ड के लिए निवेश के पसंदीदा साधन बने रहे।

### भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय स्टॉक और निधियों के प्रवाह (एफएसएफ) को शामिल करने वाले खातों को संकलित करने के लिए इस्तेमाल किया गया व्यापक फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए), 2008 के अनुसार, पांच संस्थागत क्षेत्रों<sup>2</sup> के 'किसी से-किसी के लिए' (एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू) आधार पर लिखत-वार वित्तीय खातों<sup>1</sup> को प्रस्तुत करता है (अनुबंध I)। खातों का सेट एक सुलभ लेकिन

\* भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग के अनुपम प्रकाश, कौस्तव के सरकार, ईशु ठाकुर और, सपना गोयल द्वारा तैयार किया गया। लेखक पूर्व कार्यकारी निदेशक, डॉ. मृदुल के सागर और परामर्शदाता, श्री संजय हांसदा के मसौदे पर व्यावहारिक चर्चा के लिए आभारी हैं। श्री कुणाल प्रियदर्शी और श्रीमती चैताली भौमिक के योगदान की सराहना की जाती है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

<sup>1</sup> वित्तीय खातों में वित्तीय आस्तियां और देयताएँ शामिल होती हैं जिनमें अचल संपत्तियां, भंडार, प्रावधान और आस्थगित कर शामिल नहीं होते हैं।

<sup>2</sup> पांच संस्थागत क्षेत्रों में शामिल हैं: (i) वित्तीय निगम (एफसी); (ii) गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी); (iii) सामान्य सरकार (जीजी); (iv) हाउसहोल्ड (एचएच) जिसमें गैर-लाभकारी संस्थाएँ जो हाउसहोल्ड के लिए काम कर रहीं हैं (एनपीआईएसएच) शामिल हैं; और (v) शेष विश्व (आरओडब्ल्यू)।

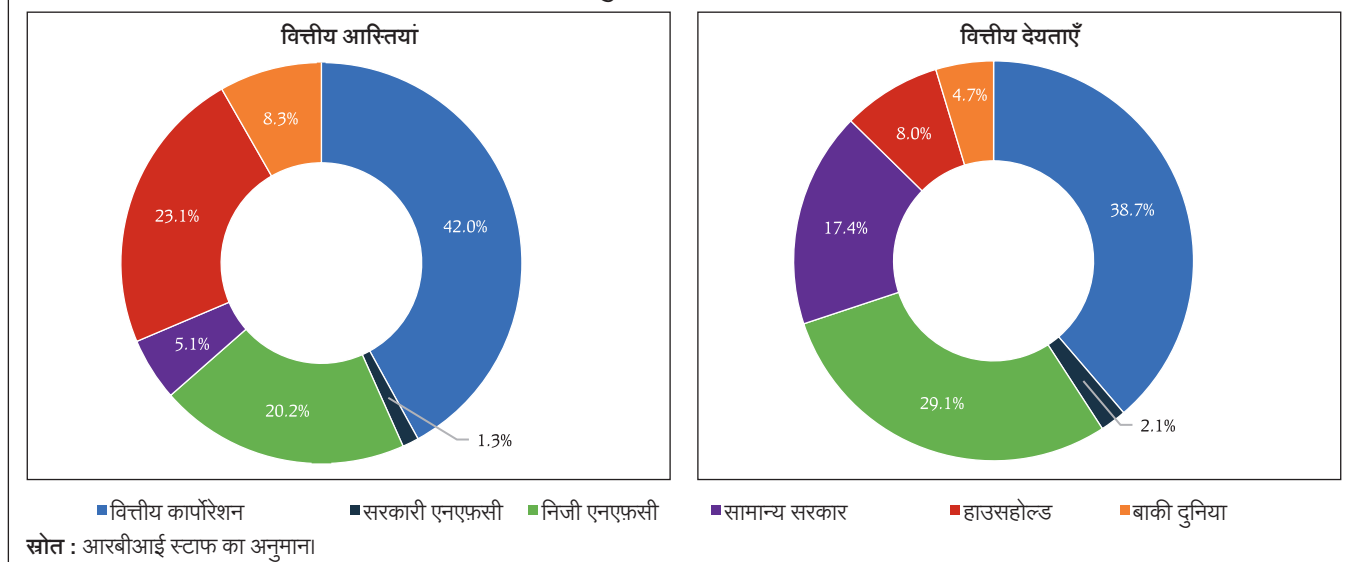
कठोर प्रारूप में अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक समष्टिआर्थिक जानकारी प्रदान करता है, और आर्थिक परिवर्तन और विकास के साथ-साथ महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं की वजह से पोर्टफोलियो समायोजन के कारण क्षेत्रों में पोर्टफोलियो बदलाव के बारे में बताता है। कोविड-19 और रुक-रुक कर होने वाले लॉकडाउन के मद्देनजर, डेटा संग्रह प्रणाली कुछ समय के लिए बाधित हो गई थी<sup>3</sup>, विशेष रूप से गैर-सरकारी गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, पद्धतिगत सुधारों के साथ संकलन को बढ़ाने और डेटा के स्रोत में सुधार करने के प्रयास निरंतर किए गए हैं<sup>4</sup>।

पिछले एक दशक में पांच संस्थागत क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह के बदलते स्वरूप ने कुल वित्तीय आस्तियों में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी को बदल दिया है, हालांकि यह मामूली है। वित्तीय आस्तियों और देयताओं दोनों में क्षेत्रीय हिस्सेदारी के मामले में, वाणिज्यिक बैंकों के प्रभुत्व वाले वित्तीय निगम (एफसी) सबसे बड़े क्षेत्र का गठन करते हैं। आस्ति के आकार के मामले में हाउसहोल्ड और निजी गैर-वित्तीय निगम (पीवीएनएफसी) उसी क्रम का पालन करते हैं, जबकि पीवीएनएफसी और सामान्य सरकार (जीजी) क्षेत्र कुल देयताओं के मामले में एफसी का पालन करते हैं। कुल आस्तियों में उनके हिस्से की तुलना में, कुल देयताओं में हाउसहोल्ड का हिस्सा बहुत कम रहता है। कुल आस्ति में सार्वजनिक एनएफसी (पीयूएनएफसी) की हिस्सेदारी 2019-20 में घटकर 1.3 प्रतिशत रह गई, जो 2011-12 में 2.0 प्रतिशत थी, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी स्थिर रही। आस्तियों और देयताओं दोनों में शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) क्षेत्र का अपेक्षाकृत मामूली हिस्सा अर्थव्यवस्था के प्रमुख हाउसहोल्ड अभिविन्यास को दर्शाता है (चार्ट 1)।

यह आलेख, संस्थागत क्षेत्रों के बीच लिखत-वार उधार और उधार संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण समझ प्रदान करने के अलावा, 2019-20 के लिए एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू आधार पर वित्तीय प्रवाह

<sup>3</sup> भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और प्रवाह: 2016-17 से 2018-19 तक जुलाई 2020 आरबीआई बुलेटिन, में प्रकाशित किया गया था।

<sup>4</sup> विस्तृत विवरण 1 से 9, संशोधित श्रृंखला 2011-12 के साथ भी इस आलेख के साथ जारी किए गए हैं।

**चार्ट 1: कुल वित्तीय आस्तियों और देयताओं की क्षेत्रीय संरचना – 2019-20**  
(कुल का प्रतिशत)

प्रस्तुत करता है। आलेख को पांच खंडों में व्यवस्थित किया गया है - खंड II जी -20 डेटा अंतराल पहल -2 (डीजीआई -2) में प्रगति को प्रस्तुत करता है और इसके बाद खंड III क्षेत्रीय वित्तीय संसाधन अंतराल का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। खंड IV वित्तीय प्रवाह के क्षेत्रीय मानचित्रण पर चर्चा करता है, और खंड V नीतिगत दृष्टिकोणों के साथ समाप्त होता है। अनुबंध I में संकलन की रूपरेखा और कार्यप्रणाली की रूपरेखा दी गई है, जबकि अनुबंध II संकलन के इस दौर में शुरू किए गए प्रमुख सुधारों को प्रस्तुत करता है।

## II. डेटा अंतराल पहल-2 के तहत प्रगति

डीजीआई-2 की छठी प्रगति रिपोर्ट, अक्टूबर 2021-दिसंबर 2021 तक उलटी गिनती<sup>5</sup> ने महामारी के कारण डीजीआई-2 कार्य कार्यक्रम में देरी को स्वीकार किया। फिर भी,

<sup>5</sup> 2021 ने जी-20 डीजीआई-2 के दूसरे चरण के अंतिम वर्ष को चिह्नित किया, और जी-20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर (एफएमसीबीजी) ने जब जीएफसी 2007-09 के दौरान पहचाने गए डेटा अंतराल को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा तैयार बीसवीं सिफारिश का समर्थन किया तब से 12वां साल।

<sup>6</sup> वित्तीय खातों के उपयोग के लिए प्रासंगिक जी-20 डीजीआई सिफारिशें, सेंट्रल बैंक सांख्यिकी, बीआईएस, 2019 पर इरविंग फिशर कमेटी में पीटर वैन डे वेन द्वारा प्रस्तुति।

भाग लेने वाली अर्थव्यवस्थाओं को सलाह दी गई थी कि वे सहमत सिफारिशों<sup>6</sup>, विशेष रूप से, क्षेत्रीय खातों पर सिफारिश II.8 को आगे बढ़ाना जारी रखें, जिसमें कहा गया है, “जी -20 अर्थव्यवस्थाओं को तिमाही और वार्षिक आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत टेम्पलेट पर आधारित क्षेत्रीय खातों के प्रवाह और तुलन पत्र को संकलित और प्रसारित करना है, जिसमें अन्य (गैर-बैंक) वित्तीय निगम क्षेत्र के डेटा भी शामिल हैं, और तुलन पत्र विश्लेषण का समर्थन करने के लिए लेनदेन और स्टॉक दोनों के लिए किसी-से-किसी के लिए मैट्रिक्स विकसित करते हैं।

प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, छह जी -20 देशों, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की और अमेरिका ने स्व-मूल्यांकन<sup>7</sup> के आधार पर वार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय खातों और तुलन पत्र के लिए लक्ष्य आवश्यकताओं को पूरा किया है। स्पेन ने वार्षिक और त्रैमासिक दोनों खातों को पूरा कर लिया है और नीदरलैंड ने विस्तृत जानकारी के साथ अपने त्रैमासिक खातों को पूरा कर लिया है। इंडोनेशिया ने 2015-19 के लिए वार्षिक और त्रैमासिक

<sup>7</sup> आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों पर अंतर-एजेंसी समूह (आईएजी), राष्ट्रीय खातों पर अंतर-सचिवालय कार्य समूह (आईएसडब्ल्यूजीएनए) के सहयोग से, जी -20 अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रगति को प्रोत्साहित करने और निगरानी करने के लिए सौंपा गया है।

क्षेत्रीय खातों और तुलन पत्र के संकलन और समन्वय को पूरा कर लिया है, जबकि चीन ने वार्षिक स्तर पर वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन दोनों के लिए निधियों के प्रवाह (एफओएफ) खाते को प्रकाशित किया है, जिससे त्रैमासिक रिपोर्टिंग की ओर धीरे-धीरे प्रगति हुई है। रूस ने वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर मुख्य वित्तीय लिखतों को प्रकाशित किया और निकट भविष्य में क्षेत्रीय और लिखत-वार विश्लेषण का विस्तार करने को प्राथमिकता दी है। वित्तीय खातों के अलावा, अमेरिका क्षेत्रीय स्तर पर गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए त्रैमासिक डेटा विकसित करने की दिशा में भी प्रगति कर रहा है।

भारत पांच संस्थागत क्षेत्रों के लिए वित्तीय तुलन पत्र का प्रसार कर रहा है और वित्तीय प्रवाह को लेनदेन और मूल्यांकन परिवर्तन (हाउसहोल्ड म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन और भविष्य निधि और केंद्रीय बैंक के लिए) में 2019<sup>8</sup> के बाद से वार्षिक आधार पर विभाजित कर रहा है, जबसे निधियों के प्रवाह में पहली बार क्षेत्र-वार बकाया के हिसाब से वृद्धि की गई। रिजर्व बैंक 1951-52 से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एफओएफ लेखा प्रकाशित कर रहा है, और 1964 से एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू के आधार पर। भारत में काम, उद्विकासी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, समय-समय पर स्थापित विभिन्न समितियों के तहत आगे बढ़ा है। वर्तमान कार्य योजना वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी समिति, 2018 (अध्यक्ष: आर.एच. ढोलकिया) की सिफारिशों द्वारा निर्देशित की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) उच्च आवृत्ति डेटा जारी करना – तिमाही और साथ ही कम अंतराल के साथ वार्षिक; (ii) नए चरों का कवरेज; और (iii) प्रवाह बनाम स्टॉक और लेनदेन बनाम मूल्यांकन जैसे नए पहलुओं का कवरेज।

2019-20 में, हाउसहोल्ड क्षेत्र के लिए तिमाही खातों का संकलन और प्रसार शुरू हुआ, जिसमें सकल हाउसहोल्ड उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में हाउसहोल्ड<sup>9</sup> की वित्तीय आस्तियों और

देयताओं के स्टॉक और प्रवाह शामिल थे। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के केंद्र सरकार (सीजी) के वित्तीय खाते से ऋण और अग्रिम और इक्विटी निवेश डेटा; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख सांख्यिकी और वित्तीय विवरणों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की आस्तियों और देयताओं के बारे में अपेक्षाकृत विस्तृत जानकारी; राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएफएससीओबी) रिपोर्ट से ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) पर जानकारी – एसटीसीबी, डीसीसीबी, पीएसी, एनएफएससीओबी<sup>10</sup> के प्रदर्शन पर मूल डेटा (अनुबंध II) इत्यादि की वजह से कुछ और सुधार संभव हुए हैं। इसके अलावा, व्यक्ति (खुदरा), उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ<sup>11</sup>) श्रेणियों की निवल बिक्री को जोड़कर हाउसहोल्ड क्षेत्र से म्यूचुअल फंड में संसाधनों का निवल प्रवाह निकाला जाता है।

### III. क्षेत्रवार वित्तीय संसाधन अंतराल

हाउसहोल्ड अर्थव्यवस्था का वित्तीय संसाधन अंतराल - वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से वित्तीय देयताओं में 2019-20 में आयी कमी में निवल वृद्धि को घटाकर मापा गया (चार्ट 2)। जबकि हाउसहोल्ड और वित्तीय निगम निवल ऋणदाता बने रहे, 2019-20 के दौरान सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों और सामान्य सरकार की निवल उधारी में वृद्धि हुई।

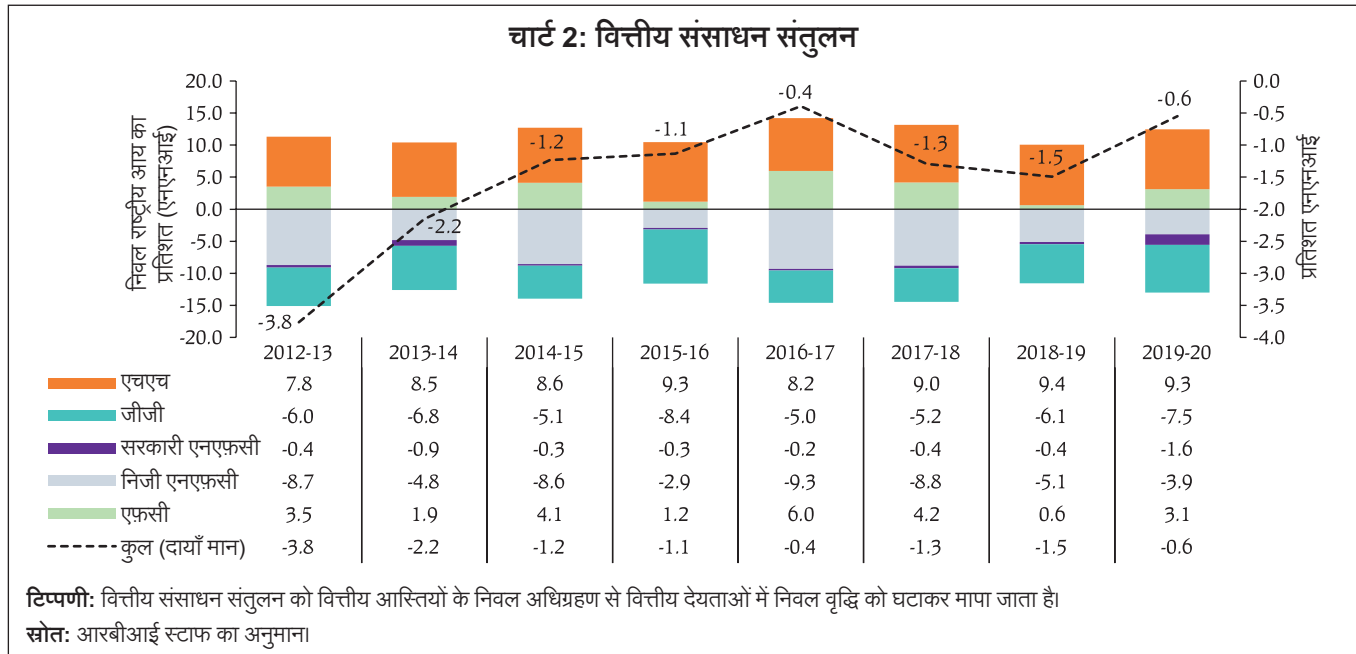
प्रत्येक क्षेत्र की वित्तीय कीमत बकाया वित्तीय आस्तियों से बकाया बाह्य वित्तीय देयताओं को घटाकर निकाली जाती है। अर्थव्यवस्था में प्रमुख बचतकर्ता और अन्य क्षेत्रों के ऋणदाता

<sup>8</sup> ऋण प्रतिभूतियों, ऋणों और इक्विटी के लिए ब्रेक-अप के साथ-साथ जीजी क्षेत्र के लिए समेकित डेटा को एफओएफ खातों के टेम्पलेट के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना है।

<sup>9</sup> आरबीआई बुलेटिन, मार्च 2022 वर्तमान सांख्यिकी, समसामयिक श्रृंखला के तहत।

<sup>10</sup> ग्रामीण सहकारी समितियों में, अल्पकालिक संस्थानों में राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) शामिल हैं।

<sup>11</sup> बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स (बीएसआर) सर्वेक्षण के अनुसार, क्रेडिट और जमा में हाउसहोल्ड के हिस्से में 'हाउसहोल्ड - अन्य' के हिस्से के रूप में एचयूएफ शामिल है। तदनुसार, हाउसहोल्ड क्षेत्र के म्यूचुअल फंड में निवल प्रवाह के लिए, एचयूएफ श्रेणी को शामिल किया गया है।



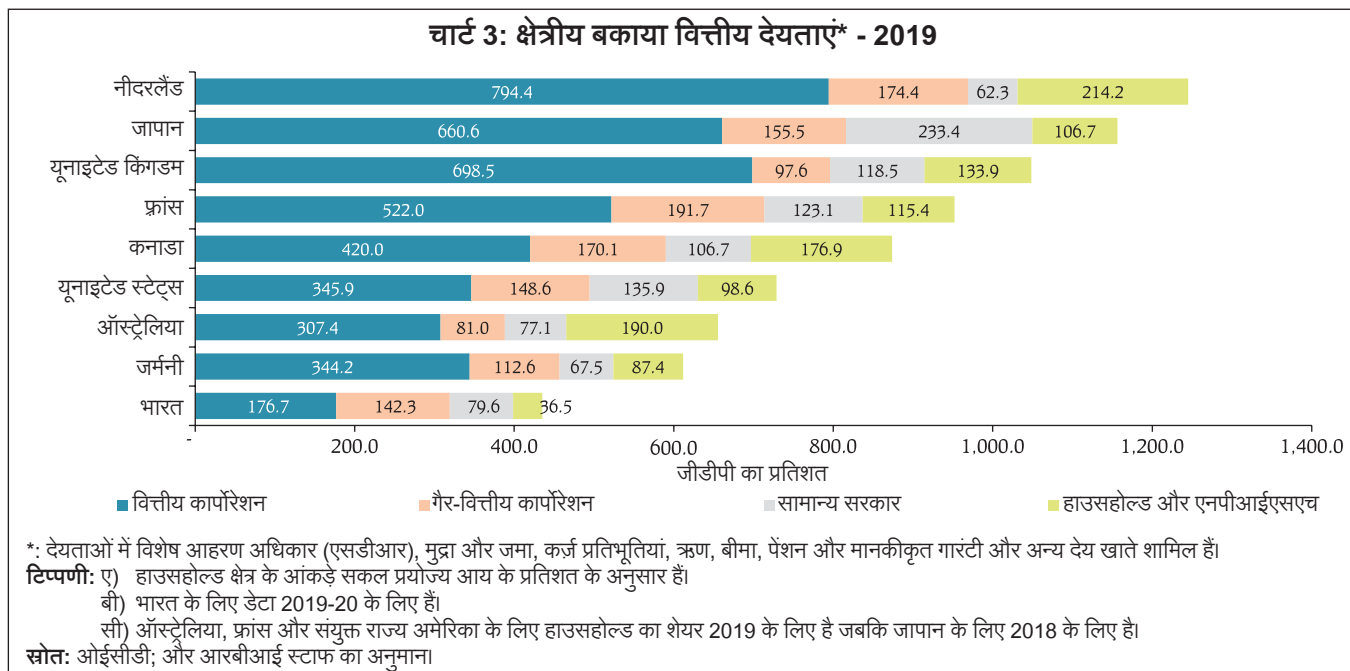
होने के कारण, हाउसहोल्ड को एफसी के बाद उच्चतम वित्तीय लगातार अर्थव्यवस्था में घाटे की स्थिति में बने हुए हैं निवल कीमत का आनंद मिलता है, जबकि जीजी और एनएफसी (सारणी 1)।

**सारणी 1: क्षेत्रीय वित्तीय निवल कीमत**  
(मौजूदा बाजार कीमतों पर एनएनआई का प्रतिशत)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>वित्तीय आस्तियाँ</b>									
1 एफसी	222.5	224.3	224.3	227.4	227.0	226.8	230.0	230.0	235.6
2 एनएफसी	162.7	150.9	123.9	120.6	122.8	109.3	125.8	111.2	120.8
2.1 सरकारी एनएफसी	11.7	10.7	9.8	8.9	8.0	7.5	7.5	7.5	7.4
2.2 निजी एनएफसी	151.0	140.2	114.0	111.7	114.9	101.8	118.3	103.8	113.4
3 जीजी	29.3	28.9	27.5	27.1	25.7	26.5	27.4	27.7	28.5
4 एचएच	123.9	121.7	120.3	122.0	122.5	122.2	124.5	127.6	129.6
5 आरओडबल्यू	46.0	48.0	50.1	50.6	49.7	45.6	45.2	44.6	46.4
<b>वित्तीय देयताएँ</b>									
1 एफसी	192.9	193.6	194.1	196.3	196.3	194.1	195.6	197.0	200.3
2 एनएफसी	165.4	162.9	145.0	144.7	136.5	129.6	139.1	129.3	133.8
2.1 सरकारी एनएफसी	12.8	12.0	11.7	10.8	10.1	9.4	9.5	9.6	11.0
2.2 निजी एनएफसी	152.6	151.0	133.2	134.0	126.4	120.2	129.6	119.7	122.9
3 जीजी	85.2	84.2	83.4	82.5	84.2	83.7	84.1	85.2	90.2
4 एचएच	39.9	39.1	38.3	37.9	37.4	37.0	38.0	39.0	41.3
5 आरओडबल्यू	21.5	20.8	22.5	23.4	23.5	21.4	21.8	21.0	24.1
<b>वित्तीय निवल कीमत</b>									
1 एफसी	29.7	30.7	30.2	31.1	30.8	32.8	34.3	33.0	35.3
2 एनएफसी	-14.4	-19.1	-20.3	-26.6	-25.9	-30.6	-36.4	-37.5	-40.4
2.1 सरकारी एनएफसी	-1.2	-1.2	-1.9	-1.9	-2.1	-1.9	-2.0	-2.1	-3.5
2.2 निजी एनएफसी	-13.2	-17.8	-18.4	-24.7	-23.8	-28.6	-34.4	-35.3	-36.8
3 जीजी	-55.8	-55.3	-55.8	-55.4	-58.5	-57.2	-56.8	-57.5	-61.7
4 एचएच	84.0	82.6	82.0	84.1	85.1	85.2	86.5	88.6	88.3
5 आरओडबल्यू	24.5	27.2	27.6	27.2	26.2	24.2	23.4	23.7	22.3

**टिप्पणी:** वित्तीय निवल कीमत की गणना बकाया वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं (शेयरधारकों की इक्विटी को छोड़कर) के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।

**स्रोत:** आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



हमारी गणना के आधार पर भारत के लिए मार्च 2020 के अंत के डेटाबेस की तुलना में ओईसीडी डेटाबेस<sup>12</sup> के आधार पर दिसंबर 2019 के अंत में बकाया वित्तीय देयताओं की स्थिति अन्य देशों की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋणग्रस्तता के उच्च स्तर को दर्शाती है (एई)। चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एफसी कुल बकाया वित्तीय देयताओं में अधिकतम हिस्सेदारी का योगदान करते हैं (चार्ट 3)।

#### IV. सभी क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह: 2019-20

क्षेत्रीय वित्तीय प्रवाह का मानचित्रण अनिवार्य रूप से संबंधित आर्थिक संस्थाओं के विशिष्ट तुलन पत्र से एकत्रित जानकारी पर आधारित है। वित्तीय वर्ष के अंत में विभिन्न वित्तीय लिखतों को जारी करने और धारण करने के स्नैपशॉट से और प्रतिपक्ष की स्थिति से क्षेत्रीय प्रवाह का पता लगाया जाता है। यह संस्थागत क्षेत्रों और निवासियों और गैर-निवासियों के बीच वित्तीय संबंधों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है, यह व्याख्या करता है कि कौन किसे, किस प्रकार के लिखत द्वारा और कितनी राशि में वित्तपोषित करता है।

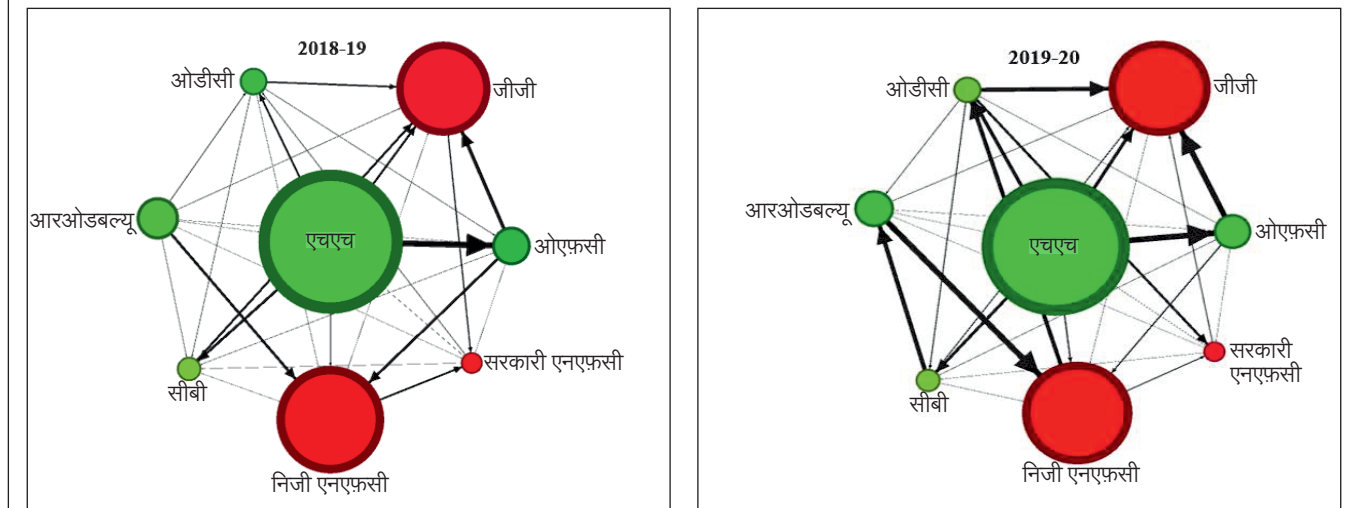
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवल प्रवाह (ऋण स्रोतों का उपयोग करता है) एक नेटवर्क प्लॉट में प्रस्तुत किया जाता है (चार्ट 4)। सापेक्ष हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद, हाउसहोल्ड और जीजी क्रमशः अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े ऋणदाता और उधारकर्ता बने हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में, अन्य निक्षेपागार निगमों (ओडीसी) और अन्य वित्तीय निगमों (ओएफसी) से जीजी में निवल प्रवाह; और 2019-20 में आरओडब्ल्यू से पीवीएनएफसी में वृद्धि हुई, जैसा कि मोटे दिशात्मक किनारों में दिखाई देता है।

वित्तीय आस्तियों में लिखत-वार निवेश

2019-20 के दौरान संसाधनों की तैनाती के लिए ऋण और अग्रिम सबसे पसंदीदा लिखत रहे, इसके बाद मुद्रा और जमा राशि का स्थान रहा। ओएफसी और रिजर्व बैंक के निवेश का एक बड़ा हिस्सा ऋण प्रतिभूतियों में था - जबकि पूर्व की सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक हिस्सेदारी थी, रिजर्व बैंक ने ज्यादातर विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश किया (चार्ट 5)। इक्विटी और निवेश निधियों के माध्यम से निवेश पर कॉर्पोरेट्स और आरओडब्ल्यू के निवेश का बोलबाला था। बीमा, पेंशन और भविष्य निधि के बाद मुद्रा और जमा हाउसहोल्ड के लिए पसंदीदा निवेश साधन बने रहे।

<sup>12</sup> वित्तीय खाते, ओईसीडी, <https://stats.oecd.org/>

चार्ट 4: क्षेत्रीय प्रवाह



**टिप्पणी:** नोड का आकार अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों की सापेक्ष बकाया निवल ऋण/उधार की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। किनारों का वजन वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में सापेक्ष क्षेत्रीय प्रवाह के शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। निवल ऋणदाता हरे रंग में दिखाई देते हैं जबकि निवल उधारकर्ता लाल रंग में।  
**स्रोत:** आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

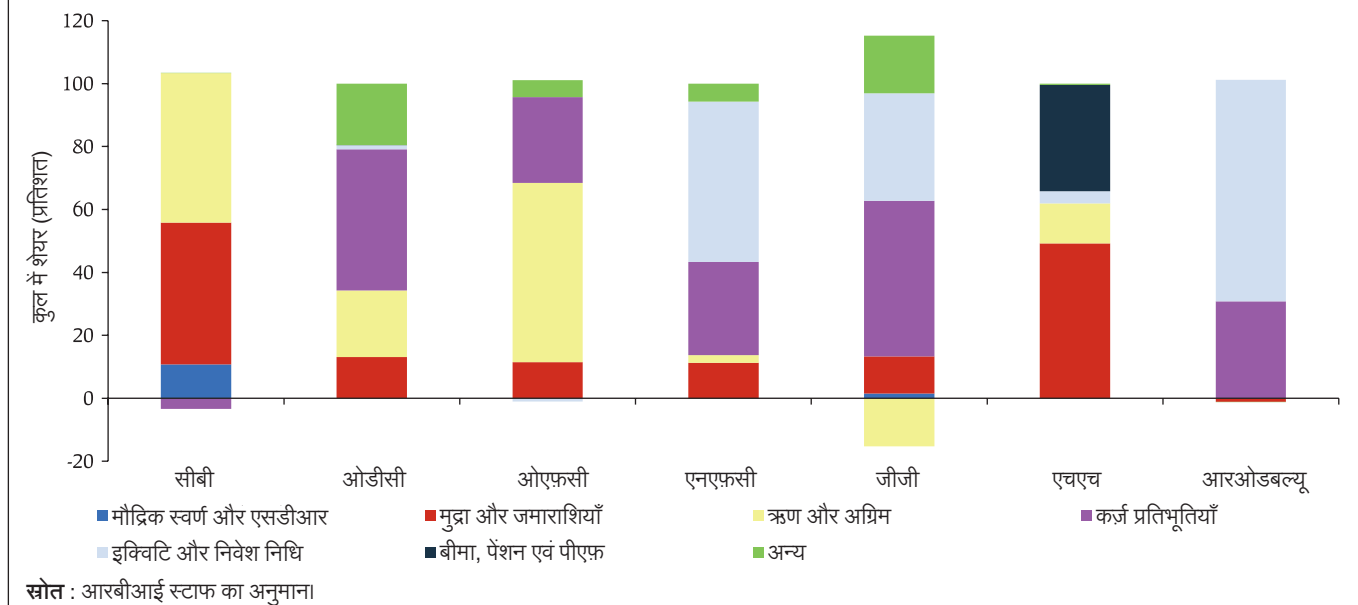
2019-20 के दौरान वित्तीय आस्तियों और देयताओं के क्षेत्र-वार प्रवाह को निम्नलिखित उप-खंडों में विस्तारित किया गया है:

IV.1 वित्तीय निगम

ओडीसी एफसी के सबसे बड़े उप-क्षेत्र का गठन करते हैं। जिनका 2019-20 में एफसी की कुल वित्तीय आस्ति का 52.1

प्रतिशत था, इसके बाद ओएफसी (36.0 प्रतिशत) और केंद्रीय बैंक (11.9 प्रतिशत) थे। ओडीसी में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के पास एफसी की कुल वित्तीय आस्ति में एक बड़ा हिस्सा (44.2 प्रतिशत) है, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की बैंक-आधारित प्रकृति को उजागर करता है। ओएफसी के अंतर्गत, प्रमुख भाग बीमा क्षेत्र का, इसके बाद गैर-जमा एनबीएफसी

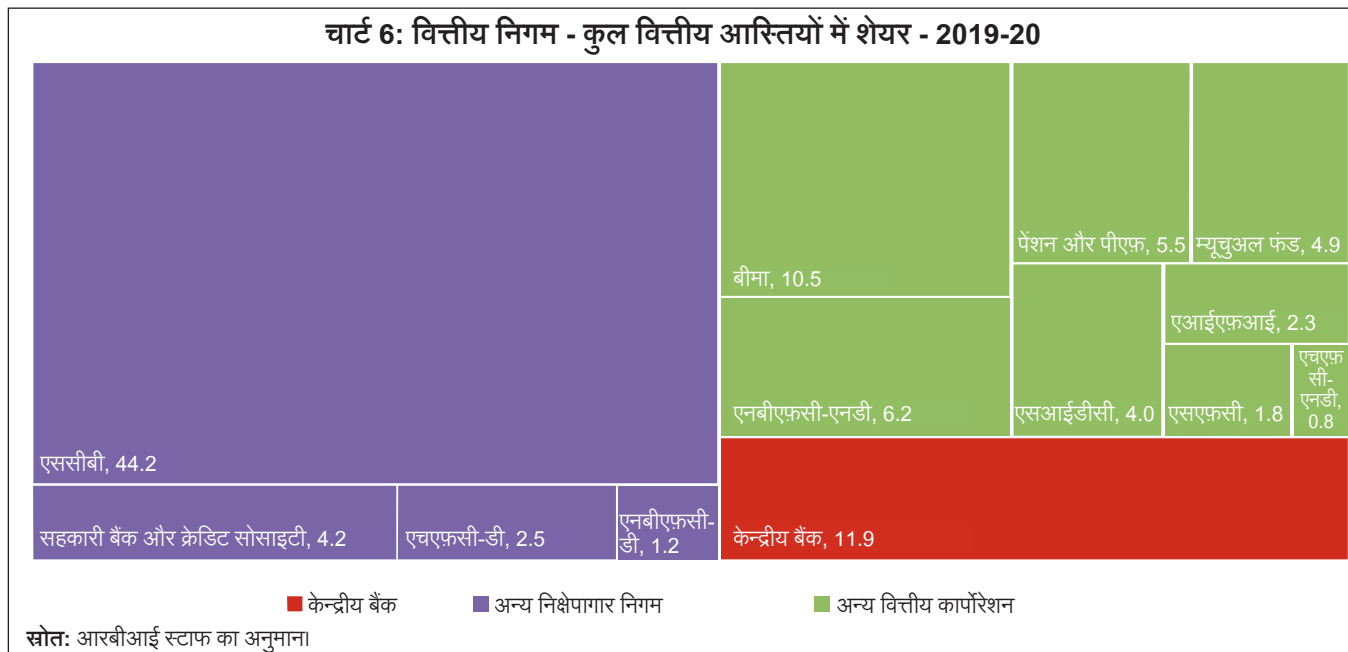
चार्ट 5: वित्तीय आस्तियों में लिखत-वार निवेश - 2019-20



**स्रोत :** आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



**चार्ट 6: वित्तीय निगम - कुल वित्तीय आस्तियों में शेयर - 2019-20**



(एनबीएफसी-एनडी), भविष्य और पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड का है (चार्ट 6)।

#### IV.1.1 सेंट्रल बैंक

रिजर्व बैंक की वित्तीय निवल संपत्ति 2018-19 में 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 7.3 प्रतिशत हो गई, साथ ही संस्थान निवल ऋण देने वाले क्षेत्रों में से एक बना रहा। 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि में मंदी को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने जून 2019 में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ से समायोजनात्मक कर दिया था। इससे बैंक की वित्तीय आस्ति में 2018-19 में जीडीपी के 21.7 प्रतिशत से 2019-20 में जीडीपी के 24.6 प्रतिशत तक का विस्तार हुआ। 2019-20 में जीडीपी। वित्तीय देयताएँ<sup>13</sup>, हालांकि, 2019-20 में बढ़कर 18.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 16.4 प्रतिशत थी।

प्रचलन में मुद्रा का प्रवाह, जो एक साल पहले कम हुआ था, 2019-20 के दौरान मामूली रूप से बढ़ा, जिससे मुद्रा-जीडीपी अनुपात 12.1 प्रतिशत हो गया। रिजर्व बैंक के पास जमाराशियों

<sup>13</sup> आरक्षित मुद्रा में प्रचलन में मुद्रा, बैंकों की जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा शामिल हैं, हालांकि, जो एक साल पहले के 14.7 प्रतिशत से 2019-20 में जीडीपी का 15.1 प्रतिशत हो गया।

में 2019-20 के दौरान वृद्धि हुई, मुख्य रूप से चलनिधि उपलब्ध कराने के कारण जिसकी वजह से रिवर्स रिपो दर में कमी के बावजूद ओडीसी के साथ रिवर्स रिपो हुआ<sup>14</sup>।

वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) की अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। स्वर्ण की होल्डिंग में वृद्धि और स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण मौद्रिक स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान एफसीए<sup>15</sup> के स्टॉक में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2018-19 में यह 2.7 प्रतिशत था। अन्य केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियों में अधिकतम वृद्धि देखी गई, इसके बाद ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का नंबर था। एफसीए ने महामारी के प्रकोप के साथ, 'सुरक्षा के लिए उड़ान' द्वारा संचालित मूल्यांकन लाभ अर्जित किया। विभिन्न चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण पिछले वर्ष में 44.1 प्रतिशत

<sup>14</sup> रिवर्स रिपो दर को 27 मार्च, 2020 को घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया था, ताकि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक के पास निष्क्रिय रूप से धन जमा करना अपेक्षाकृत अनाकर्षक हो जाए और इसके बजाय, इन निधियों का उपयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को उधार देने के लिए किया जाए (आरबीआई, 2020ए)।

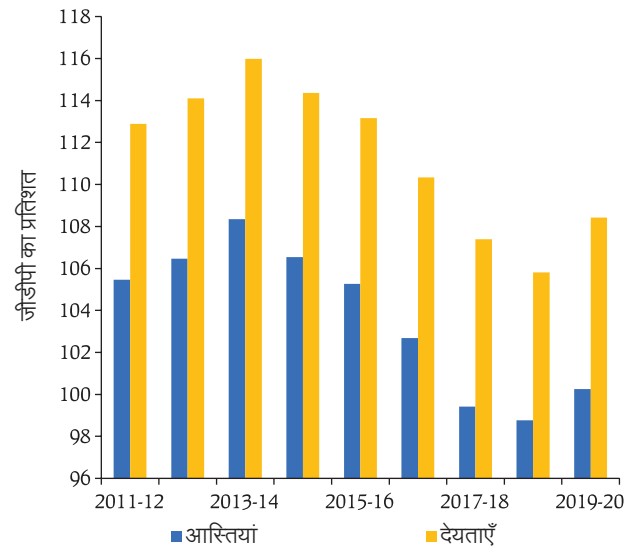
<sup>15</sup> एफसीए में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियां; (ii) बीआईएस के पास जमा; (iii) विदेशों में वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियां; (iv) विदेशी टी-बिल और प्रतिभूतियों में निवेश; और (v) भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर शामिल हैं।

की तुलना में 2019-20 में हाउसहोल्ड प्रतिभूतियों, जैसे दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और टी-बिलों में निवेश में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा कई चलनिधि बढ़ाने के उपायों में वृद्धि जैसे दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एलटीआरओ) और वर्ष के उत्तरार्ध में लक्षित एलटीआरओ के कारण ओडीसी के ऋण और अग्रिम का विस्तार हुआ।

#### IV.1.2 अन्य निक्षेपागार निगम

कारकों का एक संगम, जैसे, आर्थिक मंदी, कॉर्पोरेट तुलन पत्रों के ऋण कम करना, बैंकों की ओर से जोखिम से बचने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निरस्तीकरण से 2014-15 से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ओडीसी की वित्तीय आस्तियों में लगातार गिरावट आई थी। बेहतर आस्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी और बफर प्रावधान और लाभप्रदता पर प्रतिफल के कारण 2019-20 के दौरान एक बदलाव आया (चार्ट 7)। हालांकि, 2018-19 की तुलना में, सकल हाउसहोल्ड उत्पाद की वृद्धि में मंदी की पृष्ठभूमि में, एससीबी, सहकारी समितियों और एनबीएफसी-डी में जमा वृद्धि ने गति दी, सबसे ज्यादा कमी सहकारी बैंकों में आयी। ब्याज दरों में ढील के कारण प्रतिस्पर्धी आस्ति वर्ग आकर्षक हो गए और एक निजी क्षेत्र के बैंक से संबंधित

**चार्ट 7: ओडीसी की वित्तीय आस्तियां और देयताएँ**

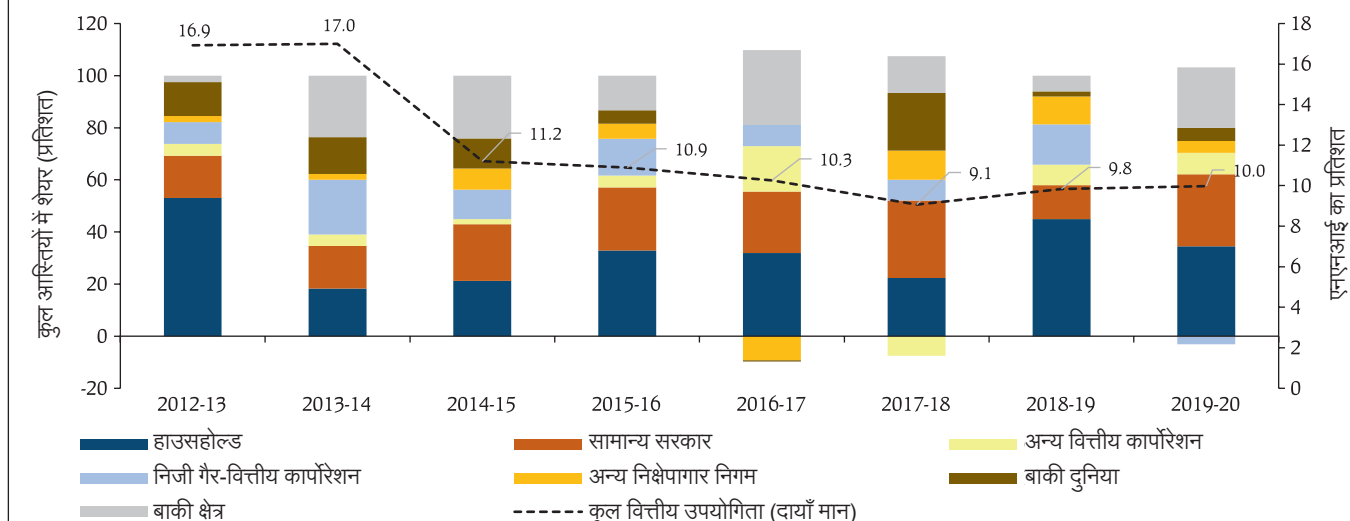


स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

ऋण-शोधन के मुद्दों ने भी फिर से थोड़ी जमाराशियाँ लाई (आरबीआई, 2020बी)।

आस्तियों के पक्ष में 2019-20 में धीमी अर्थव्यवस्था में जोखिम से बचने और सुस्त मांग दोनों को दर्शाते हुए, एससीबी द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में गिरावट आई, जबकि जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश में सुधार हुआ, जैसा कि

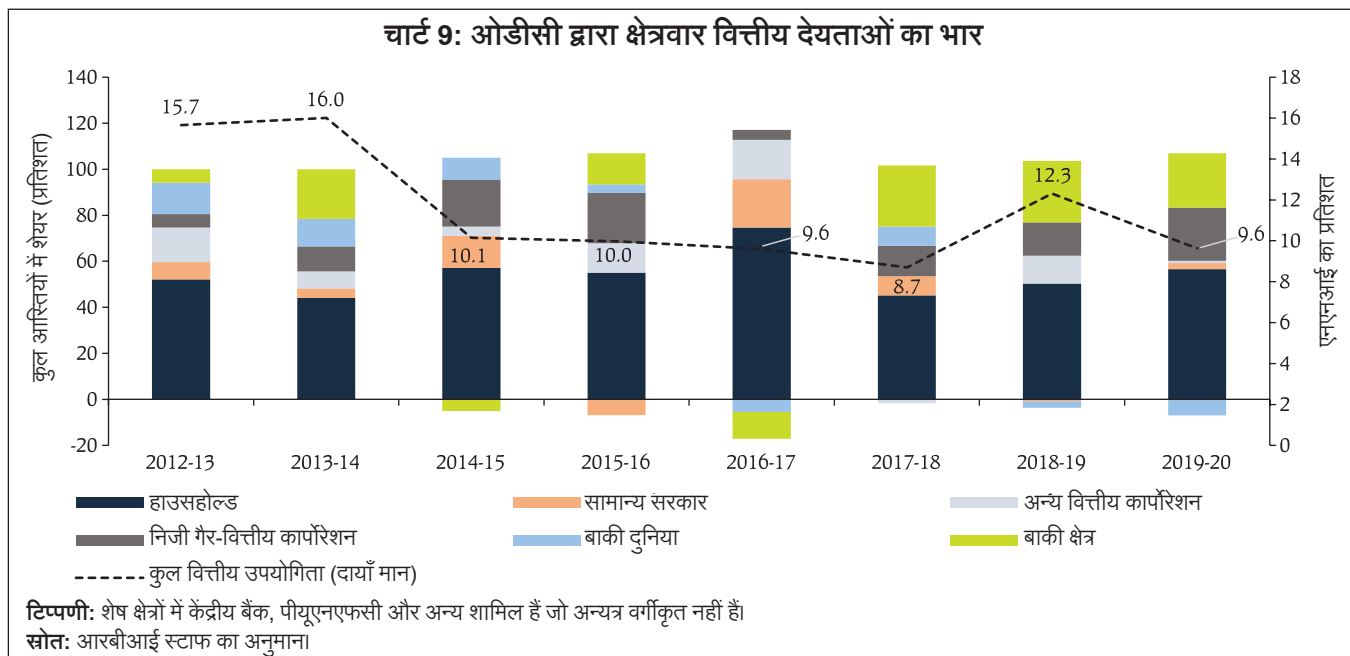
**चार्ट 8: ओडीसी की वित्तीय आस्तियों का क्षेत्र-वार प्रवाह**



टिप्पणी: शेष क्षेत्रों में केंद्रीय बैंक, पीयूएनएफसी और अन्य शामिल हैं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान





ओडीसी के समग्र रुझान में परिलक्षित होता है (चार्ट 8)। इसी स्वरूप अनुसार, एनबीएफसी-डी की ऋण वृद्धि में कमी आई, जबकि उनके निवेश - विशेष रूप से म्यूचुअल फंड में तेजी आई। एचएफसी-डी के मामले में, अचल संपत्ति क्षेत्र में बढ़ते दबाव से ऋण और अग्रिम में तेजी से कमी के कारण उनकी वित्तीय आस्तियों की वृद्धि में कमी आई है (आरबीआई, 2020बी)। सहकारी बैंकिंग संस्थानों की व्यापक पहुंच समाज के असंबद्ध और ऋण-वंचित वर्गों तक है, हालांकि, हाउसहोल्ड को दिए गए ऋणों और अग्रिमों द्वारा मुख्य रूप से संचालित 2018-19 में 3.1 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में वित्तीय आस्तियों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

हाउसहोल्ड जमा सबसे महत्वपूर्ण लिखत है जिसमें ओडीसी की देयताएँ, इसके बाद पीवीएनएफसी से जमा शामिल हैं (चार्ट 9)। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी प्रवाह को 2019-20 में बढ़ावा मिला, जिससे एससीबी में सरकार की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 41.9 प्रतिशत से बढ़कर 56.6 प्रतिशत हो गई। यह सरकार के प्रति ओडीसी की बढ़ती देयता में परिलक्षित होता था।

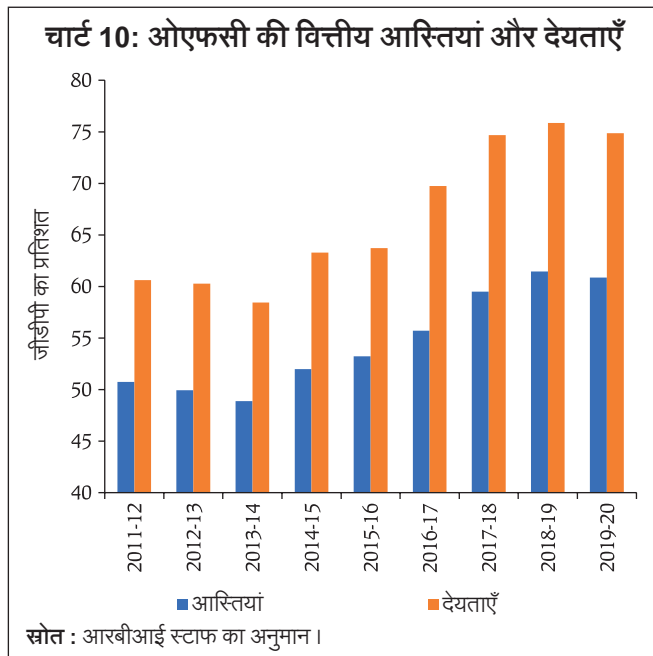
सहकारी समितियों के अंतर्गत, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) मुख्य रूप से अपनी निधि के लिए हाउसहोल्ड जमा पर निर्भर थे,

जबकि ओएफसी से उधार के साथ अन्य सहकारी समितियों से जमा ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को उनके कार्यों के वित्तपोषण में सहायता की। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) चूक और संबंधित नुकसान के संदर्भ में एनबीएफसी-डी और एचएफसी-डी दोनों के फंड के लिए बैंकों पर निर्भरता बढ़ी (आरबीआई, 2020 बी)। एचएफसी-डी द्वारा ऋणपत्र जारी करना भी 2019-20 के दौरान कम हुआ। चल रही वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वर्ष के दौरान आरओडब्ल्यू के प्रति ओडीसी की देयताएँ कम हो गईं और भारत उभरते बाजार वाले देशों के बीच उच्चतम बहिर्वाह करने वालों में से एक होने का अनुभव कर रहा है (आरबीआई, 2020 ए)।

#### IV.1.3 अन्य वित्तीय निगम

ओएफसी की वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ, जो पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही थीं, 2019-20 में जीडीपी के क्रमशः 1.0 और 0.6 प्रतिशत अंक पर सिमट गईं (चार्ट 10)। हालांकि, ओएफसी की वित्तीय आस्तियों और देयताओं की वृद्धि में कमी को वर्ष के दौरान दर्ज की गई कम जीडीपी वृद्धि के मुकाबले देखा जाना चाहिए।

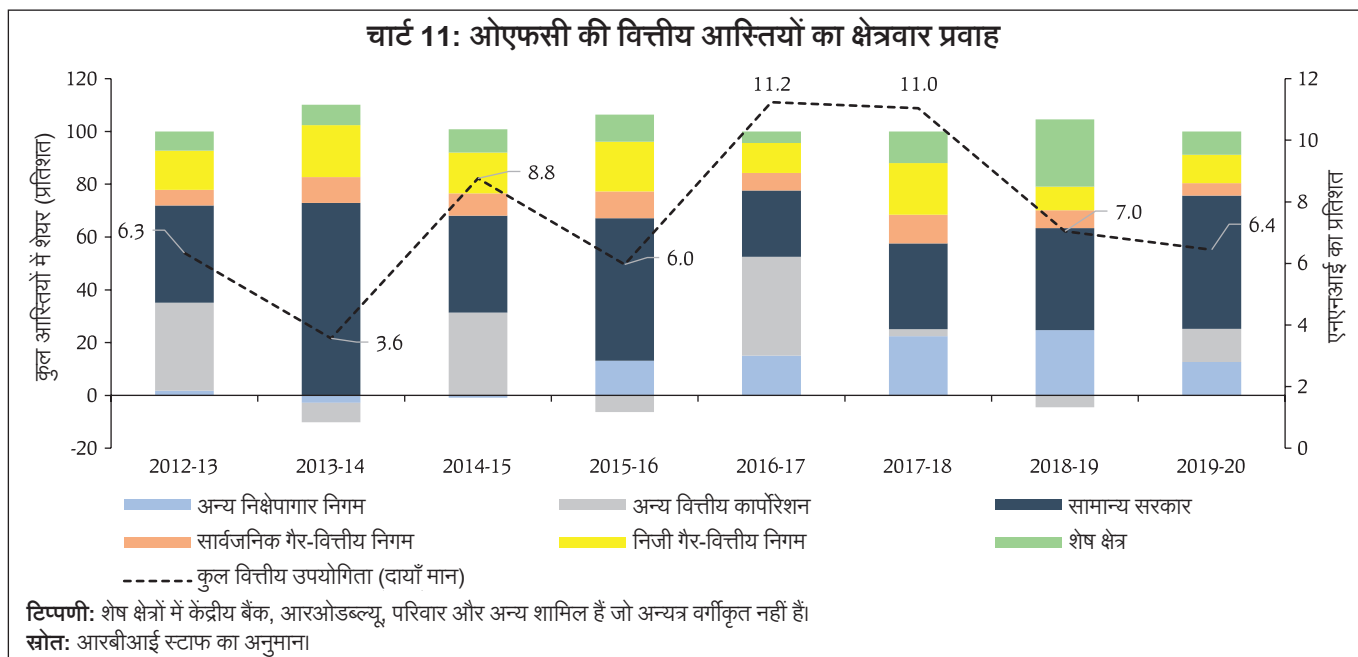
एचएफसी-एनडी ने अपनी वित्तीय आस्तियों और देयताओं में मामूली संकुचन देखा, जबकि एनबीएफसी-एनडी के मामले में



एनबीएफसी-एनडी की विदेशी देयताओं में बढ़ोतरी रिजर्व बैंक द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मानदंडों में ढील के कारण आसान हुई, इससे उन्हें विदेशी फंड तक पहुंचने में मदद मिली (आरबीआई, 2020 बी)। चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई)<sup>16</sup> की देयताएँ जो ओएफसी का एक हिस्सा हैं, मुख्य रूप से ओडीसी की जमा राशि, ओएफसी, ओडीसी और सीजी की ऋण प्रतिभूतियों और सीजी के इक्विटी शेयरों द्वारा संचालित होती हैं। जबकि सिडबी में बहुसंख्यक इक्विटी होल्डिंग (लगभग 85 प्रतिशत) ओडीसी और ओएफसी के पास है, अन्य तीन के मामले में सीजी का पूरा स्वामित्व है।

फरवरी-मार्च 2019-20<sup>17</sup> में शेयर बाजार में गिरावट के कारण ओएफसी के तुलन पत्र में इक्विटी और निवेश फंड की बाजार कीमतों में काफी कमी आई है। जीजी प्रतिभूतियाँ साथ ही 2019-20 में अंतर-क्षेत्रीय उधार हाल के वर्षों में ओएफसी के लिए अनुकूल निवेश का मार्ग बने रहे(चार्ट 11)। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की चपेट में आने पर आईएल एवं एफएस प्रकरण के बाद आत्मविश्वास में कमी, चलनिधि दबाव और रेटिंग में गिरावट

वृद्धि पिछले दो वर्षों में दोहरे अंकों की वृद्धि की तुलना में 2019-20 में घट गई। एनबीएफसी-डी के रुझानों का अनुसरण करते हुए, आईएलएंडएफएस चूक और संबंधित डाउनग्रेड के बाद एनबीएफसी-एनडी के लिए ऋण पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है।



<sup>16</sup> नाबार्ड, एक्विजि बैंक, सिडबी और एनएचबी एआईएफआई हैं।

<sup>17</sup> <https://www.thehindubusinessline.com/markets/stock-markets/market-rout-mutual-funds-equity-assets-halve-in-march/article31273736.ece>;  
<https://www.paytmoney.com/blog/amfi-mutual-fund-report-march/>

और तेज हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 में एनबीएफसी-एनडी की आस्ति वृद्धि में पर्याप्त गिरावट आई (आरबीआई, 2020बी)। मुख्य रूप से सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा संचालित, बीमा और भविष्य निधि की सकल वित्तीय आस्तियों ने 2019-20 में अपनी बढ़ती प्रवृत्ति को जारी रखा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निवेश पर अधिसूचना<sup>18</sup> के बाद, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की ओर निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) दोनों ने अपने ग्राहक आधार में वृद्धि दर्ज करते हुए 2019-20 में पेंशन फंड की वित्तीय संपत्ति में वृद्धि की। एआईएफआई के मामले में, हाउसहोल्ड को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ऋण और अग्रिम में व्यापक रूप से वृद्धि हुई।

#### IV.2 गैर-वित्तीय निगम

अधिकांश आस्तियां गैर-वित्तीय प्रकृति की होने के कारण, एनएफसी की वित्तीय निवल संपत्ति उनकी कुल निवल संपत्ति से काफी कम है। समग्र स्तर पर, पीयूएनएफसी का वित्तीय संसाधन अंतराल 2018-19 में (-) 0.4 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में (-) 1.6 प्रतिशत हो गया, जबकि पीवीएनएफसी में सुधार हुआ जो पिछले वर्ष के (-)5.1 प्रतिशत से (-) 3.9 प्रतिशत हो गया। 2019-20 में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा बढ़ी हुई उधारी ने पीयूएनएफसी की वित्तीय देयताओं को उपर खींचा। दूसरी ओर, इक्विटी निवेश और अन्य खाता प्राप्तियों के मूल्य में गिरावट के कारण वित्तीय आस्तियों में वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है।

पीवीएनएफसी - कुल वित्तीय आस्तियों और देयताओं के आकार के मामले में एफसी और हाउसहोल्ड के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र - 2019-20 में अर्थव्यवस्था की वित्तीय आस्तियों का 20.2 प्रतिशत था। पीवीएनएफसी द्वारा वित्तीय देयताओं की वृद्धि ने आस्ति अधिग्रहण के साथ-साथ 2018-19 से वृद्धि का प्रदर्शन किया। लिखतों के संदर्भ में, एफसी से ऋण और उधार, इक्विटी के बाद पीवीएनएफसी के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत रहा है।

<sup>18</sup> श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की अधिसूचना संख्या 1071 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2015 ने ईपीएफओ द्वारा इक्विटी और संबंधित निवेश में 5 से 15 प्रतिशत निवेश निर्धारित किया है (निफ्टी और सेंसेक्स के ईटीएफ)।

#### IV.3 सामान्य सरकार<sup>19</sup>

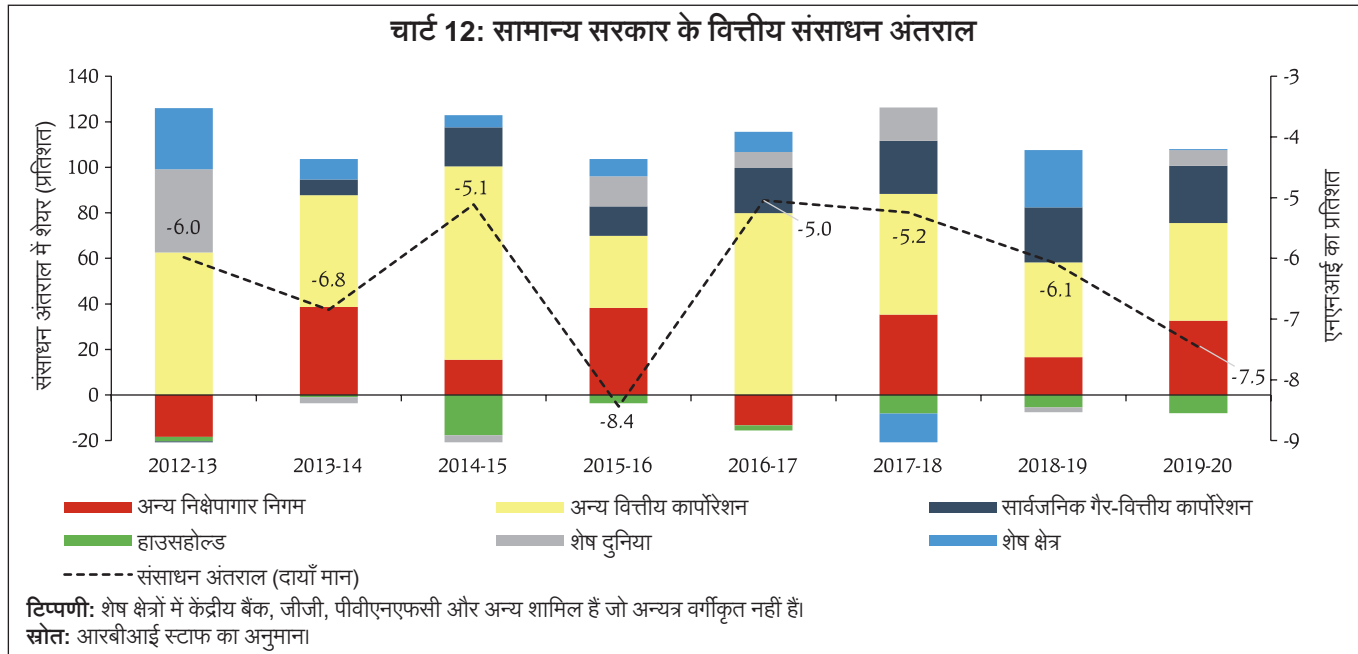
जीजी और एनएफसी नकारात्मक संसाधन शेष वाले केवल दो क्षेत्र हैं। जबकि जीजी की वित्तीय आस्ति सकल हाउसहोल्ड उत्पाद के 25 प्रतिशत तक मामूली रूप से सुधरी, वित्तीय देयताएँ 2019-20 में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गईं, जिनमें से सीजी की देयताएँ सकल पारिवारिक उत्पाद के 53 प्रतिशत तक थीं। इसके अलावा, वित्तीय देयताओं में वृद्धि वित्तीय आस्तियों में उल्लेखनीय 3.4 प्रतिशत अंक से आगे निकल गई।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अधिकांश ऋणों को विपणन योग्य ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से वित्तपोषित करती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से ओडीसी, ओएफसी और हाउसहोल्ड द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है (चार्ट 12)। पिछले वर्षों की तरह, 2019-20 के दौरान ऋण प्रतिभूतियों का सब्सक्रिप्शन स्वरूप समान रहा। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जो बिना लाभ और हानि के आधार पर काम करता है और सरकार से सब्सिडी और अनुदान के माध्यम से भी समर्थन प्राप्त करता है, उसे सीजी<sup>20</sup> के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2016-17 के बाद से एफसीआई द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) उधार, जिसे सीजी द्वारा उधार माना जाता है, मार्च 2020 के अंत तक ₹ 2,54,600 करोड़ था। राज्य सरकारों के मामले में, जबकि उनकी निवल बाजार उधारी में वृद्धि हुई लगभग 40 प्रतिशत, सकल बाजार उधार 32.7 प्रतिशत बढ़ा (आरबीआई, 2020सी)।

सीजी की आस्ति संरचना पर तीन लिखतों का प्रभुत्व है, अर्थात् इक्विटी निवेश (35.9 प्रतिशत); ऋण और अग्रिम (28.6 प्रतिशत); और ऋण प्रतिभूतियां (18.0 प्रतिशत)। पिछले एक दशक में, सीजी का निवेश पोर्टफोलियो ऋण प्रतिभूतियों से हटकर इक्विटी और ऋण और अग्रिम में चला गया। विशेष रूप से, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों (आरबीआई को छोड़कर) में सीजी की इक्विटी 21.9 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में लगभग ₹3.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹4.4 लाख करोड़ हो

<sup>19</sup> जीजी में केवल सीजी और राज्य सरकारें शामिल हैं।

<sup>20</sup> एसएनए 2008 एक सार्वजनिक निगम, या सरकार द्वारा नियंत्रित निगम को किसी अन्य सार्वजनिक इकाई/सरकार द्वारा नियंत्रित निगम के रूप में परिभाषित करता है और यह एक बाजार निर्माता भी है, यानी एक इकाई जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीमतों पर अपने सभी या अधिकांश उत्पादन दूसरों को प्रदान करती है। एफसीआई का शत-प्रतिशत स्वामित्व सीजी के पास है और यह लाभ कमाने वाला निगम नहीं है जिसमें संपूर्ण निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए है। उपरोक्त वर्गीकरण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, एफसीआई को सीजी के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

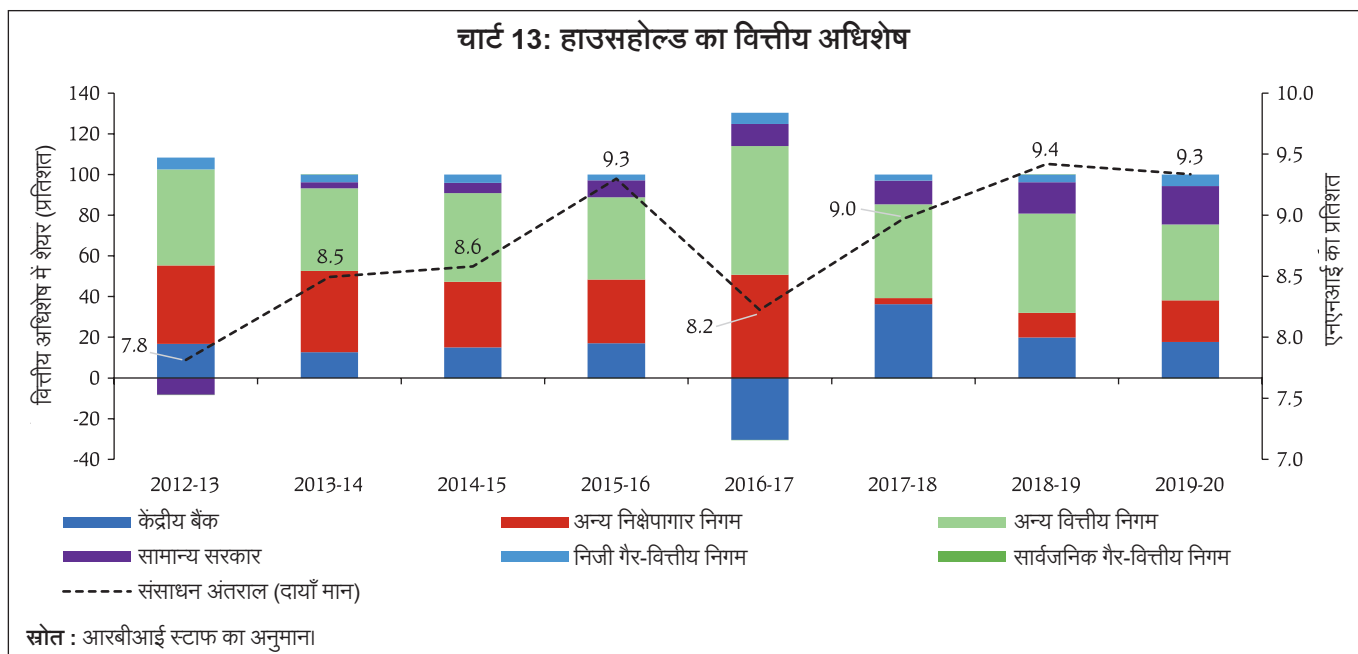


गई। राज्य सरकारों के लिए, उनकी अधिकांश वित्तीय आस्तियां जमा के रूप में होती हैं, उसके बाद इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों का स्थान होता है।

#### IV.4 हाउसहोल्ड (एनपीआईएसएच सहित)

हाउसहोल्ड, उपभोग व्यय का सबसे बड़ा स्रोत होने के अलावा, अर्थव्यवस्था में वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियों में

निवेश के लिए वित्तीय अधिशेष में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वित्तीय आस्तियों में तेज गिरावट के साथ वित्तीय आस्तियों और हाउसहोल्ड क्षेत्र की देयताओं दोनों में वृद्धि 2019-20 में कमजोर हुई। परिणामस्वरूप, 2019-20 में हाउसहोल्ड क्षेत्र का वित्तीय अधिशेष 0.1 प्रतिशत अंक से थोड़ा कम होकर एनएनआई के 9.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट 13)।



विवेकाधीन व्यय में कमी और स्थिर/कम आय के बावजूद एहतियाती/जबरन बचत में संबंधित वृद्धि के कारण 2020-21 में हाउसहोल्ड वित्तीय बचत में जीडीपी के 11.6 प्रतिशत की वृद्धि ने पहले ही हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों में बढ़ोतरी की पुष्टि कर दी है। वित्तीय आस्तियों के प्रवाह में ओडीसी की हिस्सेदारी, जो 2017-18 में एक नगण्य स्तर तक कम हो गई - पुनर्मुद्रीकरण के कारण हाउसहोल्ड द्वारा बड़ी मात्रा में नकदी की निकासी हुई - जो 2019-20 में लगभग 21 प्रतिशत तक बढ़ गई। विशेष रूप से पहली तिमाही में, गैर-आवश्यक उपभोग व्यय के कारण, 2020-21 में इस उछाल के और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, परिवारों से बीमा क्षेत्र तक संसाधनों का एक स्थिर प्रवाह बनाए रखा जाता है, जिसके 2020-21 में और बढ़ने की संभावना है।

जमा और बीमा की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, 2019-20 में हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद इक्विटी, मुद्रा, ऋण प्रतिभूतियां और म्यूचुअल फंड में निवेश है। निवेश फंडों के प्रति हाउसहोल्ड की प्राथमिकता में बदलाव उनके बकाया आस्तित्व मूल्य में दीर्घकालिक वृद्धि में भी परिलक्षित होता है, हालांकि, मार्च 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली के बाद गिरावट आई है।

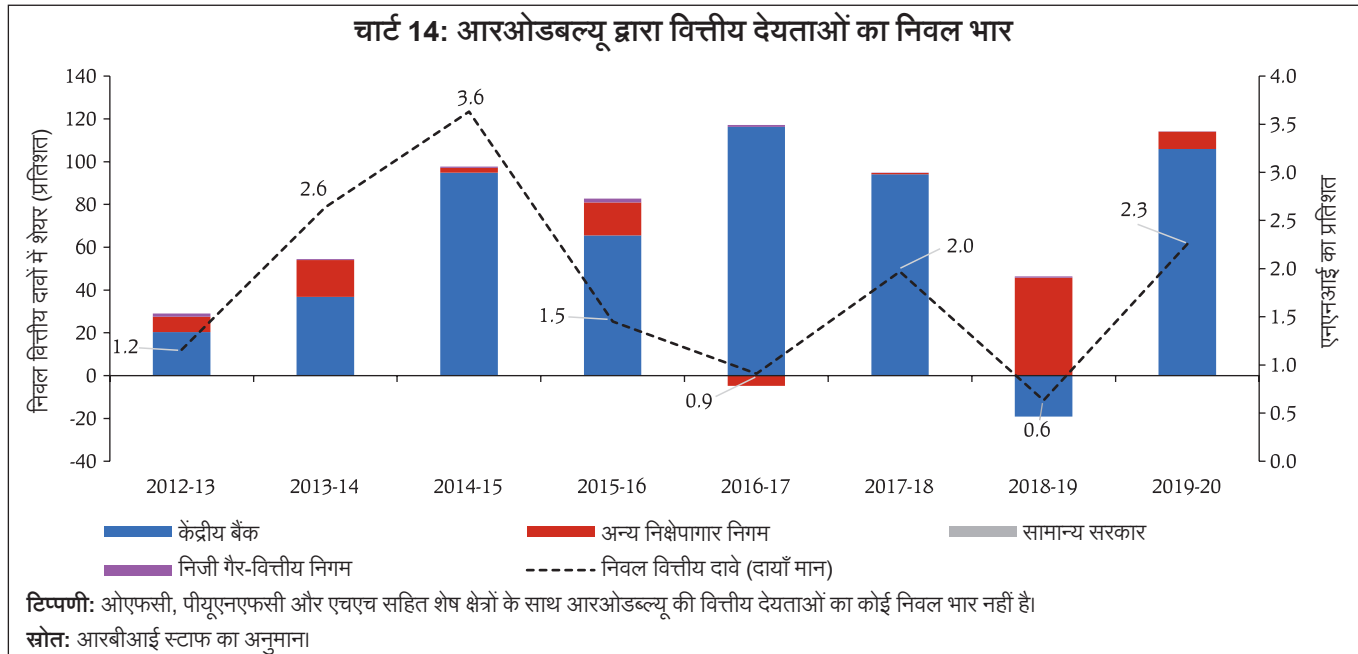
#### IV.5 शेष विश्व

भारत 2019-20 में आरओडब्ल्यू से निवल कर्जदार बना रहा। हालांकि, विदेशी संसाधनों पर निर्भरता एक साल पहले की तुलना में 2019-20 में कम हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच कम व्यापार घाटे और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों की वजह से और वैश्विक निवेश चिंताओं में वृद्धि के कारण भारत के चालू खाते के घाटे (सीएडी) को 2018-19 में (-) 2.1 प्रतिशत से कम करके 2019-20 में जीडीपी के (-)0.9 प्रतिशत तक सीमित करने की पुष्टि की गई है। अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विदेशी पूंजी के प्रमुख स्रोतों में वृद्धि हुई और निवल पूंजी अंतर्वाह निम्न सीएडी को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था।

मार्च 2020 के अंत तक, आरओडब्ल्यू की कुल वित्तीय देयताओं का दो-तिहाई रिजर्व बैंक के लिए आरक्षित आस्ति<sup>21</sup>, विशेष रूप से प्रतिभूतियों और अन्य केंद्रीय बैंकों के पास जमा के रूप में था। आरक्षित आस्तियों के अलावा, लगभग एक तिहाई ऋण प्रतिभूतियों और इक्विटी के रूप में एनएफसी की ओर था। आरओडब्ल्यू की देयताएँ 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 प्रतिशत बढ़ी, जिसका मुख्य कारण विदेशों में जारी ऋण प्रतिभूतियों में रिजर्व बैंक की सब्सक्रिप्शन में वृद्धि थी (चार्ट 14)।

आरओडब्ल्यू द्वारा एनएफसी की इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों का अधिग्रहण 2019-20 में मजबूत रहा। इसके अलावा, भारत निरंतर आर्थिक सुधारों के बल पर, 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गति को बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह बड़े पैमाने पर वैश्विक विकास से प्रभावित था और सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा कई विश्वास निर्माण उपायों के बावजूद, 2019-20 की शुरुआत से अस्थिर रहा। कोविड-19 के मद्देनजर वैश्विक जोखिम से बचने की एक अभूतपूर्व लहर के कारण वित्तीय वर्ष के अंत तक निवल बिकवाली हुई। वास्तव में, 2019-20 की चौथी तिमाही में ईएमई से बहिर्वाह सुरक्षा के लिए अब तक की सबसे बड़ी उड़ान थी। विदेशी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए, जैसे, एफपीआई निवेश की सीमा में वृद्धि, विदेशी निवेशकों के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना, एफपीआई द्वारा सीजी प्रतिभूतियों (टी-बिल सहित) और राज्य विकास ऋणों में अल्पकालिक निवेश में वृद्धि। इन उपायों ने मार्च 2020 के अंत तक एफपीआई बहिर्वाह को काफी हद तक उलटने में मदद की। प्रचुर मात्रा में वैश्विक चलनिधि, अनुकूल विदेशी ब्याज दरों और उदारीकरण उपायों जैसे कारकों के संयोजन से 2019-20 में मजबूत ईसीबी अंतर्वाह हुआ। कुल मिलाकर, 2019-20 में

<sup>21</sup> आरक्षित आस्तियों में मौद्रिक स्वर्ण, एसडीआर होल्डिंग्स, आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, मुद्रा और जमा, प्रतिभूतियां और अन्य दावे शामिल हैं।

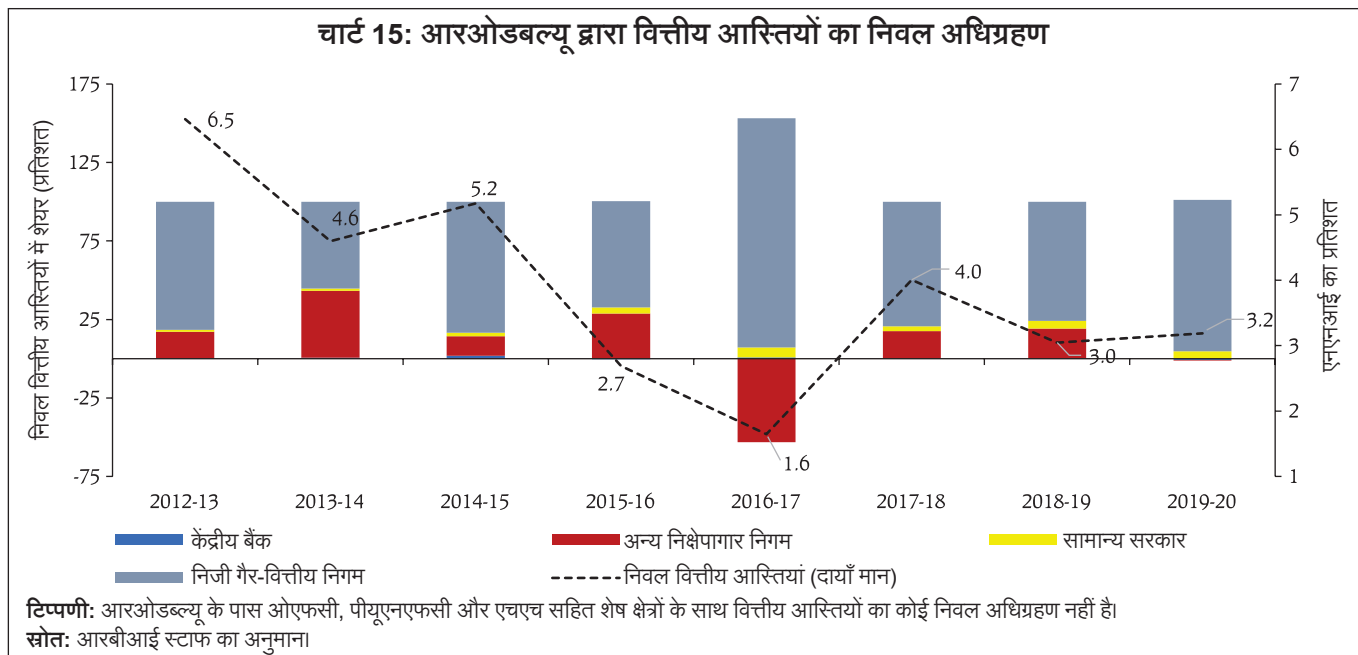


आरओडब्ल्यू द्वारा आस्तियों का निवल अधिग्रहण 2018-19 के स्तर पर लगभग स्थिर रहा (चार्ट 15)।

**V. निष्कर्ष**

वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से वित्तीय देयताओं में निवल वृद्धि को घटाने से प्राप्त, अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधन

अंतराल में 2019-20 में कमी आयी। हाउसहोल्ड और वित्तीय निगमों ने घाटे वाले क्षेत्रों को बाह्य निधिकरण की कम आवश्यकता के साथ चलनिधि प्रदान करना जारी रखा। 2019-20 में आरओडब्ल्यू से निवल उधारी में तेजी से गिरावट आई। रिज़र्व बैंक का वित्तीय संसाधन संतुलन सकारात्मक क्षेत्र में रहा – जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में





सामान्य मंदी की पृष्ठभूमि में समय पर और उचित चलनिधि सहायता सुनिश्चित करता है। अधिशेष संसाधन उत्पन्न करने के मामले में अन्य निक्षेपागार निगमों के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय आस्ति गुणवत्ता में वृद्धि और बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए में गिरावट को दिया जा सकता है। गैर-जमा लेने वाले खंड के भीतर, एनबीएफसी-एनडी के मामले में विकास पिछले दो वर्षों में दर्ज दो अंकों की वृद्धि की तुलना में 2019-20 में कम हो गया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की वित्तीय देयताएँ बढ़ गईं जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा राज्य सरकारों की तुलना में अधिक रहा।

आगे बढ़ते हुए, महामारी वर्ष 2020-21 में व्यवधानों से निपटने के लिए शुरू किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय, क्षेत्रों की निवल ऋण/उधार की स्थिति को प्रभावित करेंगे। सरकारी क्षेत्र के संसाधन कई महामारी लहरों के मद्देनजर किए गए व्यापक राजकोषीय सहायता उपायों के प्रभाव को दर्शाएंगे। अप्रत्याशित आर्थिक और वित्तीय आघातों से निपटने के लिए एक अवरोध प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बफर की प्रासंगिकता अधिक स्पष्ट हो सकती है और यह रिज़र्व बैंक के वित्तीय खातों में परिलक्षित होगी। 23 अगस्त, 2021 को आईएमएफ द्वारा भारत को आबंटित एसडीआर 12.57 बिलियन का तदनुसार संबंधित क्षेत्रों जैसे केंद्रीय बैंक, केंद्र सरकार और बाकी दुनिया के वित्तीय खातों पर असर होगा। केंद्र सरकार द्वारा आस्ति मुद्रीकरण और उच्च बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय जैसी नीतिगत पहल सार्वजनिक और निजी दोनों गैर-वित्तीय निगमों की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। महामारी प्रतिबंधों के कारण, कृषि को छोड़कर, बैंक ऋण को व्यापक रूप से मंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि, देयताओं के पक्ष में, बैंकों ने उच्च जमा वृद्धि दर्ज की, जो विवेकाधीन खर्च में गिरावट के कारण हाउसहोल्ड क्षेत्र की वित्तीय बचत में वृद्धि में परिलक्षित हुई। 2020-21 में महामारी से प्रेरित मंदी के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था ने संकुचित व्यापार घाटे के कारण 2003-04 के बाद पहली बार चालू खाता अधिशेष दर्ज किया।

जबकि हाउसहोल्ड और वित्तीय निगमों से उच्च वित्तीय अधिशेष उत्पन्न करना जारी रखने की उम्मीद है, कॉर्पोरेट और बैंकों की बेहतर तुलन पत्र स्थिति अधिक डिजिटलीकरण द्वारा समर्थित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों के उच्च प्रवाह की सुविधा प्रदान कर सकती है।

### संदर्भ

FSB (2021), "G20 Data Gaps Initiative (DGI-2) The Sixth Progress Report – Countdown to December 2021" International Monetary Fund and Financial Stability Board, <https://www.fsb.org/2021/10/g20-data-gaps-initiative-dgi-2-the-sixth-progress-report-countdown-to-december-2021/>

Government of India (2020), "Union Budget 2020-2021", Ministry of Finance, Government of India, <https://www.indiabudget.gov.in/budget2020-21/index.php>

NABARD (2020), "Annual Report 2019-20", National Bank for Agriculture and Rural Development, <https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/1008203730Nabard%20English%20Annual%20Report%20for%20Website.pdf>

National Statistical Commission (2018), "Report of the Committee on Financial Sector Statistics", Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India, [https://mospi.gov.in/documents/213904/0/Report\\_of\\_the\\_Committee\\_on\\_Financial\\_Sector\\_Statistics-2182018+%281%29.pdf/4d759d97-08d8-425e-4ea8-71474ac2f8c7?t=1595174128318](https://mospi.gov.in/documents/213904/0/Report_of_the_Committee_on_Financial_Sector_Statistics-2182018+%281%29.pdf/4d759d97-08d8-425e-4ea8-71474ac2f8c7?t=1595174128318)

OECD (2017), "Understanding Financial Accounts", Edited by Peter Van De Ven and Daniele Fano, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264281288-en>.

Prakash, Anupam, Anand Prakash Ekka, Kunal Priyadarshi, Chaitali Bhowmick and Ishu Thakur (2020), "Financial Stocks and Flows of the Indian

*Economy:2016-17 to 2018-19*", RBI Bulletin, July 2020, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/1FINANCIALSTOCKS76894282D5104115A83911082958A7B9.PDF>

RBI (2015), *Manual on the Compilation of Flow of Funds Accounts of the Indian Economy*", Reserve Bank of India, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/FM2190C3DC5C5442C587DF978335851933.PDF>

RBI (2020a), *Annual Report 2019-20*", Reserve Bank of India, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/ORBIAR201920DA64F97C6E7B48848E6DEA06D531BADE.PDF>

RBI (2020b), *Report on Trend and Progress of Banking in India 2019-20*", Reserve Bank of India, [https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/ORTP2020\\_F3D078985540A4179B62B7734C7B445C9.PDF](https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/ORTP2020_F3D078985540A4179B62B7734C7B445C9.PDF)

RBI (2020c), *State Finances: A Study of Budgets of 2020-21*", Reserve Bank of India, [https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/OSF\\_271020FCF77451F1DF744B2B244875C785B8EF3.PDF](https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/OSF_271020FCF77451F1DF744B2B244875C785B8EF3.PDF)

SNA (2008), *System of National Accounts*", United Nations, the European Commission, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the International Monetary Fund, and the World Bank Group, <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>

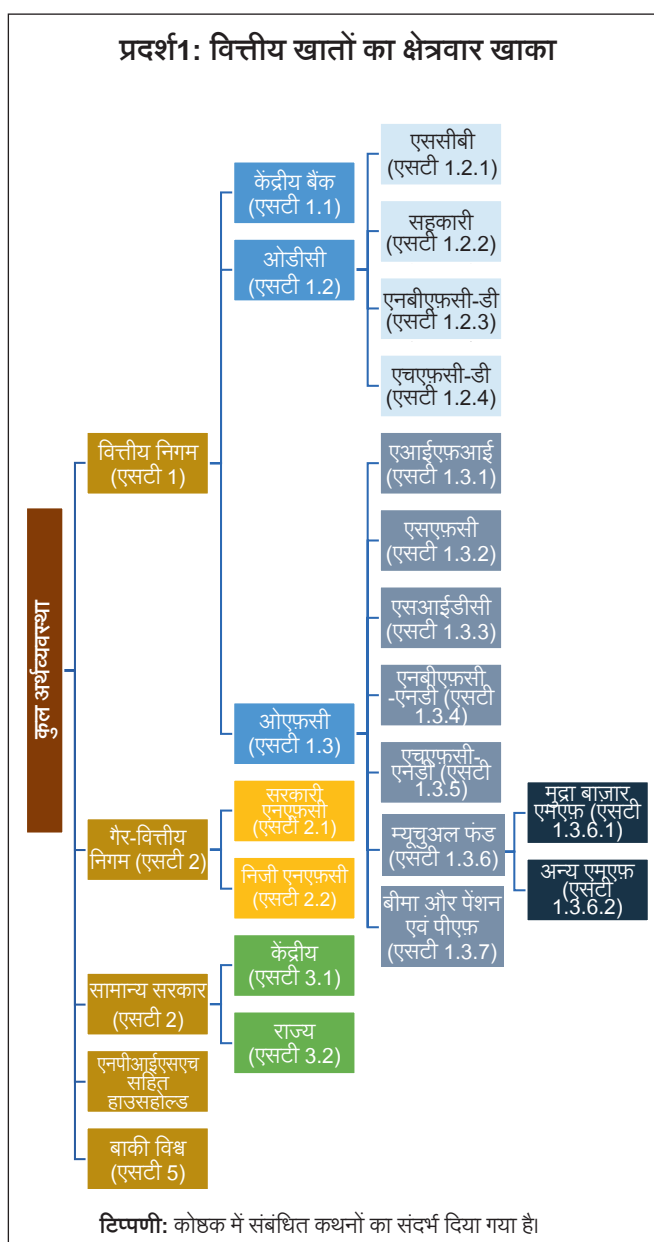
## अनुबंध I:

### भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक की रूपरेखा और निधियों का प्रवाह

#### अर्थव्यवस्था के संस्थागत क्षेत्र

विस्तृत क्षेत्रीय वर्गीकरण प्रदर्श 1 में प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय निगम क्षेत्र में ऐसे निगम शामिल हैं जो मुख्य रूप से वित्तीय मध्यस्थता या बीमा और पेंशन फंड सहित सहायक वित्तीय गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह बचतकर्ताओं से निवेशकों के लिए फंड को चैनलाइज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



इस क्षेत्र को उनके कार्य और वित्तपोषण के प्रकार के आधार पर उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - केंद्रीय बैंक जो वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है; ओडीसी जो जमा के रूप में देयताओं के माध्यम से वित्तीय मध्यस्थता में संलग्न हैं; और ओएफसी।

गैर-वित्तीय निगम क्षेत्र में निगमित कानूनी संस्थाएं शामिल हैं जो गैर-वित्तीय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शामिल हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों गैर-वित्तीय निगम शामिल हैं जो सीमित देयता के साथ सूचीबद्ध या असूचीबद्ध हो सकते हैं।

सामान्य सरकारी क्षेत्र में सभी सरकारी विभाग, कार्यालय और अन्य निकाय शामिल होते हैं जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा स्वयं के सामूहिक उपभोग के लिए (जैसे, लोक प्रशासन, सुरक्षा पुलिस, आदि) और जनता द्वारा व्यक्तिगत उपभोग के लिए (जैसे, स्वास्थ्य और शिक्षा) वस्तुओं और सेवाओं के गैर-बाजार उत्पादन में शामिल होते हैं। इस क्षेत्र को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में वर्गीकृत किया गया है।

हाउसहोल्ड क्षेत्र अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में और वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियों में एक निवेशक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, इसमें एनपीआईएसएच शामिल है जो गैर-बाजार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।

आरओडबल्यू क्षेत्र में सभी अनिवासी संस्थागत इकाइयाँ शामिल हैं, चाहे वह अनिवासी सरकारें हों, निगम हों, या व्यक्ति हों, जो निवासी इकाइयों के साथ लेन-देन करते हों, या जिनके निवासी इकाइयों के साथ अन्य आर्थिक संबंध हों।

#### वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण

एफएसएफ खाते को संकलित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय लिखत (सारणी ए.1) एसएनए 2008 में निर्दिष्ट लिखतों की सूची के अनुरूप हैं, जिन्हें समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ समूहीकृत किया गया है।

**सारणी ए.1: वित्तीय लिखतों का वर्गीकरण**

एसएनए 2008 संहिता	वित्तीय लिखत
F1 एफ11 एफ12	मौद्रिक स्वर्ण और एसडीआर मौद्रिक स्वर्ण एसडीआर
F2 एफ21 एफ22 + एफ29	मुद्रा और जमा मुद्रा जमा
F3	कर्ज प्रतिभूतियों
F4	ऋण
F5 एफ51 एफ52	इक्विटी और निवेश फंड शेयर/इकाइयाँ इक्विटी निवेश फंड शेयर/इकाइयाँ
F6 एफ61 एफ62 एफ63 एफ64 एफ66	बीमा, पेंशन और मानकीकृत गारंटी योजनाएं गैर-जीवन बीमा तकनीकी भंडार जीवन बीमा और वार्षिकी पात्रताएं पेंशन पात्रता पेंशन प्रबंधकों पर पेंशन निधि का दावा मानकीकृत गारंटी के तहत कॉल के लिए प्रावधान
F8 एफ81 एफ89	प्राप्य/देय अन्य खाते व्यापार क्रेडिट और अग्रिम प्राप्य/देय अन्य खाते

मौद्रिक स्वर्ण केंद्रीय बैंक द्वारा विशेष रूप से स्वर्ण बुलियन के रूप में बिना किसी दायित्व के आरक्षित आस्ति है। इसी तरह, एसडीआर अंतरराष्ट्रीय आरक्षित आस्तियां हैं, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं और मौद्रिक प्राधिकरण मौद्रिक स्वर्ण के पूरक हैं।

नोट और सिक्कों से युक्त मुद्रा केंद्रीय बैंक (घरेलू मुद्रा) और अनिवासी अधिकारियों (विदेशी मुद्रा) की देयताएँ हो सकती हैं।

जमा में बैंक खाते, मांग जमा, बचत और सावधि जमा जैसे लिखत शामिल हैं। यह केंद्रीय बैंक, ओडीसी और आरओडब्ल्यू की देयताएँ हो सकती हैं।

ऋण प्रतिभूतियों में परक्राम्य लिखत शामिल हैं, जैसे, टी-बिल, वाणिज्यिक पत्र, बांड, और आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां जो ऋण के प्रमाण के रूप में काम करती हैं।

ऋण गैर-परक्राम्य वित्तीय आस्तियां हैं जिनमें ओवरड्राफ्ट, किस्त ऋण, आईएमएफ पर दावे या देयताएँ, और रिपो समझौते जैसे उपकरण शामिल हैं।

इक्विटी और निवेश फंड शेयर के मालिक को पूर्व निर्धारित राशि का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि इन लिखतों के जारीकर्ता की आस्ति पर केवल एक अवशिष्ट दावे के लिए प्रदान करते हैं। निवेश फंड शेयर सामूहिक निवेश वाहनों द्वारा जारी किए जाते हैं जो वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियों में निवेश के लिए धन जमा करते हैं और मुद्रा बाजार और गैर-मुद्रा बाजार फंड शेयरों में विभाजित होते हैं।

बीमा, पेंशन और मानकीकृत गारंटी योजनाओं में जीवन और गैर-जीवन बीमा और वार्षिकी पात्रताएं, पेंशन और गैर-पेंशन पात्रताएं शामिल हैं। ये बीमा और पेंशन फंड उप-क्षेत्रों में देयताएँ हैं और योजनाओं में प्रतिभागियों की आस्तियां हैं।

प्राप्य या देय अन्य खातों में व्यापार ऋण और निगमों, सरकार, हाउसहोल्ड और एनपीआईएसएच, और आरओडब्ल्यू को दिए गए अग्रिम और कर, लाभांश, सामाजिक योगदान, मजदूरी और वेतन से संबंधित अन्य प्राप्य या देय शामिल हैं।

## अनुबंध II: कार्यप्रणाली और डेटा स्रोतों में परिशोधन

वित्तीय स्टॉक और निधियों के प्रवाह का संकलन, जिसमें डेटा स्रोतों की एक विशाल विविधता शामिल है, यह जानकारी की अनुपलब्धता, माप त्रुटियों और असंगतताओं के कारण कुछ सीमाओं के अधीन है। नतीजतन, सांख्यिकीय विसंगतियां कुल स्रोतों और भले ही उन्हें कम करने के प्रयासों के बावजूद धन के उपयोग के बीच अंतर के रूप में उभरती हैं। फिर भी, विसंगतियों को कम करने के लिए लिखत-वार विवरण के साथ संस्थागत आंकड़ों का समय पर संकलन और उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। संकलन के इस दौर में, पेश किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:

- एसएनए 2008 के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय लेनदेन के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे प्रतिपक्ष देयता नहीं बनाते हैं। तदनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय देयताओं के रूप में नहीं माना गया है।
- ऋण और अग्रिम, और इक्विटी निवेश के लिए डेटा के बेहतर स्रोतों का उपयोग करके सीजी की वित्तीय आस्तियों को संशोधित किया गया है। एसएनए 2008 के अनुरूप, संपूर्ण एसडीआर आवंटन को सीजी की देयता के रूप में माना गया है।
- मौजूदा प्रथा के अनुसार, आरआरबी खातों को भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति (आरटीपी) पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से एकत्रित योगों का उपयोग करके संकलित किया जाता था। क्षेत्रीय मानचित्रण के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र से परिकल्पित शेयरों का इस्तेमाल किया गया था। इस आलेख में, नाबार्ड की रिपोर्ट - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुख सांख्यिकी और वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है।
- आरआरबी के समान, आरसीबी के लिए एफएसएफ खाते का संकलन आरटीपी से योग का उपयोग करके किया गया था। वर्तमान आलेख में इसके बजाय आरसीबी के विभिन्न स्तरों के लिए क्षेत्रीय शेयरों की गणना के लिए एनएफएससीओबी की जानकारी का उपयोग किया गया है।
- एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, व्यक्ति (खुदरा), उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) श्रेणियों की निवल बिक्री को जोड़कर म्यूचुअल फंड में हाउसहोल्ड क्षेत्र का निवल प्रवाह निकाला गया है।